

भारत द्वारा अफगानस्तान को सहायता

प्रलम्बिस के लिये:

अफगानस्तान-2020 सम्मेलन, अमेरिका और तालबान शांति समझौता

मेन्स के लिये:

अफगानस्तान को लेकर भारत की रणनीति में बदलाव, अमेरिका और तालबान शांति समझौते का भारत पर प्रभाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'अफगानस्तान-2020 सम्मेलन' के अवसर पर भारत ने अफगानस्तान में विकास कार्यों के लिये 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लगभग 150 परियोजनाओं की घोषणा की है।

- इस सम्मेलन में अफगानस्तान के राष्ट्रपति, संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ के अधिकारियों के साथ विश्व के अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किया।
- गौरतलब है कि अमेरिका ने 20 जनवरी, 2021 तक अफगानस्तान में तैनात अपने सैनिकों की संख्या को 2500 तक सीमित करने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बडि:

भारत की वर्तमान सहायता:

- भारत द्वारा उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं के चौथे चरण की शुरुआत की जाएगी, जिसमें 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लगभग 150 परियोजनाएँ शामिल हैं।
- भारत ने अफगानस्तान के साथ शहतूत बांध (Shahtoot Dam) के निर्माण के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं, गौरतलब है कि इस बांध के माध्यम से काबुल शहर के 20 लाख लोगों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।

पूर्व में दी गई सहायता:



- अफगानस्तान में भारत की विकास परियोजनाएँ पाँच स्तंभों पर आधारित रही हैं:
 - बड़ी अवसंरचना परियोजनाएँ।

- मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण।
 - मानवीय सहायता।
 - उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाएँ।
 - हवाई और भू-संपर्क के माध्यम से व्यापार और नविश में वृद्धि।
- वर्ष 2002 से लेकर अब तक भारत ने अफगानिस्तान के विकास और पुनर्निर्माण की दशा में 3 बिलियन डॉलर (लगभग 2,200 करोड़ रुपए) खर्च किये हैं।
 - अफगानिस्तान की स्थलरुद्ध भौगोलिक स्थिति इसके विकास में सबसे बड़ी बाधा रही है, साथ ही पाकिस्तान द्वारा परागमन को बाधित किये जाने से यह स्थिति और भी बदतर हो गई है।
 - भारत द्वारा ईरान के [चाबहार बंदरगाह](#) के माध्यम से अफगानिस्तान को संपर्क का एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान किया गया है।
 - **महामारी सहयोग:** COVID-19 महामारी की चुनौती से निपटने के लिये भारत द्वारा अफगानिस्तान को 20 टन दवाइयों और अन्य आवश्यक उपकरणों के साथ 75,000 टन गेहूँ की आपूर्ति की गई है।

भारत के दृष्टिकोण में बदलाव:

- ध्यातव्य है कि भारत द्वारा अफगानिस्तान में तालबान के शासन के दौरान (वर्ष 1996 से वर्ष 2001) कोई नविश नहीं किया गया।
- परंतु वर्तमान में जब यह स्पष्ट हो गया है कि भविष्य में तालबान-अफगानिस्तान प्रमुख शक्ति बनकर उभर सकता है तो ऐसे समय में भारत द्वारा अफगानिस्तान में नविश के नरिणय को इसके दृष्टिकोण में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।
- भारत ने सितंबर 2020 में कतर की राजधानी दोहा में आयोजित अंतर-अफगान वार्ता के प्रारंभ समारोह में भी भाग लिया था, जहाँ तालबान की 21 सदस्यीय टीम भी उपस्थित थी। यह अफगानिस्तान की राजनीतिक शक्ति संरचना और ज़मीनी वास्तविकता में हो रहे बदलाव को लेकर भारत की स्वीकार्यता को दर्शाता है।

अमेरिकी सैनिकों की संख्या में कटौती:

- ध्यातव्य है कि फरवरी 2020 में दोहा में अमेरिका और तालबान ने एक [शांति समझौते](#) पर हस्ताक्षर किये थे।
 - इस समझौते के तहत अमेरिका ने अगले 14 महीनों के अंदर अफगानिस्तान में तैनात अपने सभी सैनिकों को वापस बुलाने और अफगान सरकार द्वारा गरिफ्तार किये गए तालबानी लड़ाकों को रिहा करने पर सहमत व्यक्त की थी।
 - इसके बदले में तालबान ने आशवासन दिया कि वह अफगानिस्तान को अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे अंतरराष्ट्रीय ज़हिदी संगठनों द्वारा अपने बेस के रूप में उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा। इसके साथ ही तालबान ने अफगान सरकार के साथ सीधी बातचीत शुरू करने के लिये भी अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी।
 - ऐसे महत्त्वपूर्ण समय में अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान को छोड़कर जाना न सिर्फ अफगान सैनिकों को आवश्यक सहयोग (वशिषकर वायुशक्ति) से वंचित करेगा बल्कि यह उनके मनोबल को भी प्रभावित करेगा।
 - [उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन](#) (नाटो) ने अफगान सैनिकों को अगले चार वर्षों के लिये वित्त पोषण प्रदान करने के लिये प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
 - हालाँकि यह नरिणय अफगानिस्तान को एक अनिश्चित भविष्य की ओर अग्रसर करेगा क्योंकि इस बात की संभावनाएँ बहुत अधिक हैं कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालबान देश की सत्ता को अपने हाथों में लेने का प्रयास करेगा।
 - वर्ष 2001 में अफगानिस्तान में अमेरिकी हमले के बाद सत्ता से हटाए जाने के बाद से वदिशी लड़ाकों और अफगान सरकार दोनों के बीच संघर्ष जारी है।
 - वर्तमान में देश के आधे से अधिक हिस्से पर तालबान का अधिकार है और वह इसके पूरे हिस्से को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने के लिये संघर्ष कर रहा है।
 - इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद से तालबान ने देशभर में 13000 से अधिक हमले किये हैं।
 - अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन (**UN Assistance Mission in Afghanistan-UMAMA**) की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020 के शुरुआती 9 महीनों में लगभग 6,000 अफगान नागरिकों की हत्या हुई है और इसमें से 45% हत्याएँ तालबान के द्वारा की गई थी।

आगे की राह:

- अफगानिस्तान में हिंसा का बढ़ता स्तर एक बड़ी चिंता का विषय है। हालाँकि अनेक, चुनौतियों के बावजूद, दोनों पक्ष (सरकार के प्रतिनिधित्व तथा तालबान) बातचीत की राह पर अग्रसर हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों पक्ष एक प्रारंभिक सफलता तक पहुँच भी गए हैं।
- भारत ने अफगानिस्तान में तत्काल एवं व्यापक युद्ध वरिाम का आह्वान किया है और भारत हमेशा से इस बात का समर्थक रहा है कि यह शांति प्रक्रिया अफगान के नेतृत्व, अफगान के स्वामित्व और अफगान के नियंत्रण में होनी चाहिये।
- भारत एक शांतिपूर्ण, समृद्ध, संप्रभु, लोकतांत्रिक और एकजुट अफगानिस्तान की दशा में काम करने हेतु अफगानिस्तान के लोगों तथा विश्व समुदाय के साथ हाथ-से-हाथ मिलाकर चलने के लिये तत्पर है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

